the beneficiary is to be allowed to 1 select an animal of his choice and he j can himself make payment to the guP- J pliex direct against cash receipt. The acquisition of the animal would be verified by the field staff of bank.

Reaction of IFWJ t_0 Bachawat Wage Board

285. SHRI DHULESHWAR MEENA: SHRI CHATURANAN MISHRA-. SHRI N. E. BALARAM:

WAI the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Federation of Working Journalists has impressed upon Governrnent that serious industrial unrest in newspaper organisations would ensue if Government accept the irrational and anti-labour recommendations of th_e Bachawat Wage Board regarding interim relief;

(b) whether it is also a fact that IFWJ hag demanded the replacement of Shri Bachawat as Chairman of the Wage[1] Board; and

(c) if so, what ig Governmenf's reaction thereto and what decision, if any, has been taken by Government im this re- j gard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI p. A. SANGMA); (a) and (b)Yes, Sir.

(c) The Government have notified the interim relief 15 per cent of basic wages subject to minimum of Rs. 90|-p.m. as against a. rate of 7.5 per cent subject to a. minimum of Rs. 45|- p.m. recommended by Wage Boards.

देश में कपड़ा मिलें

286. **श्री मीर्ज़ा इर्शाद बेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) सरकार कितनी मिलें चलाती है; और

(ग) कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मई 1986 के अन्त तक देश में सूती वस्त्र मिलों (राज्य-वार) की संख्या निम्नांकित प्रकार है :--

राज्य	मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	55
आसाम	2
बिहार	6
गुजरात	116
हरियाणा	17
जम्मू और काश्मीर	1
कर्नाटक	43
केरल	28

राज्य	मिलों की संख्या
मध्य प्रदेश	24
महाराष्ट्र	114
उड़ीसा	9
पंजाब	20
राजस्थान	34
तमिलनाडु	439
उत्तर प्रदेश	49
पश्चिमी बंगाल	42
दिल्ली	4
पांडिचेरी	6
गोवा	1
हिमाचल प्रदेश	3
मनीपुर	1
	1014

(ख) अपने-अपने अभिकरणों की मार्फत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा चलाई जा रही सूती वस्त्र मिलों की संख्या 164 है ।

(ग) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जून, 1985 में सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति के अनुसार सरकार द्वारा कई उपाय उठाए गए हैं ।

उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग को 31 मार्च 1986 तक आई डी बी आई द्वारा 439.43 करोड़ रु. की सुलभ ऋण की अदायगी ।

(2) अगले पांच वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 750 करोड़ रु. का आधुनिकीकरण कोष का सृजन ।

(3) पूर्ण फाइबर लोचशीलता की अनुमति ।

(4) आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं तथा आधुनिकीकरण के प्रकार का, जिसे वस्त्र उद्योगद्वारा अपनाया जाना चाहिए, पता लगाने के लिए आधुनिकीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना ।

(5) सम्भाव्य तौर पर अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिए बनाये जाने वाले पुनःस्थापन पैकेज तैयार करने तथा प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना ।

(6) अच्छी क्वालिटी की मशीनरी बनाने के लिए स्वदेशी वस्त्र मशीनरी विनिर्माता क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

(7) स्वदेश में न बनायी जाने वाली अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के ओ जी एल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति ।

(8) निर्यात बाध्यता से सम्बद्ध बड़े पने वाले शटल रहित करघों तथा रोटर स्पिनिंग मशीनों के रियायती आयात शुल्क पर आयात की अनुमति ।

देश में हथकरघा-एककः

287. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हथकरघा-एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है; इन एककों में कितने व्यक्ति नियोजित हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने नये एककों को खोला या बन्द किया गया है;

(ख) इस समय हथकरघा-क्षेत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इस क्षेत्र द्वारा जनता कपड़ा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ग) क्या सरकार हथकरघा-क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) देश में हथकरघा क्षेत्र विकेन्द्रीकृत है और कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता है । इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए अथवा बन्द हुए हथकरघा एककों के कोई आंकड़े नहीं हैं । अलग-अलग समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर देश में हथ-करघों की कुल संख्या अनुमानतः लगभग 30 लाख है । हथकरघों का राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (नीचे देखिये) 1985-86 के दौरान हथ-करघा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या अनन्तिम तौर पर अनुमानतः 78.5 लाख है ।

(ख) 1985-86 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में अनन्तिम तौर पर अनुमानतः 36800 लाख मीटर का उत्पादन हुआ है । गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार हुआ है:-

वर्ष	उत्पादन लाख वर्गमीटर में
1983-84	3483.40
1984-85	3567.70
1985-86	3981.20 (अन्तिम)

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है:-

(1) प्राथमिक सहकारी समितियों में शेयर पूंजी अंशदान के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता ।

(2) प्राथमिक सहकारी समितियों, एपैक्स सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता ।

(3) प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान ।

(4) हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए आधुनिकीकरण सहायता ।

(5) करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात् संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता ।

(6) जनता कपड़ा योजना ।

(7) विशेष छूट योजना ।

(8) हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता ।

(9) विशेष पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाएं ।

(10) थ्रिफ्ट कोष योजना ।

(11) कार्यशाला-सह-आवास योजना ।